साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 36 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 24 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

वैश्विक प्लास्टिक संधि- क्या प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से भावी पीढ़ियों को बचाएगी संधि?

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और यदि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो अनुमान है कि 2050 तक यह दोगुना या तिगुना हो जाएगा। हर दिन दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में 2,000 ट्रकों के बराबर प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। इस सप्ताह 23 से 29 अप्रैल 2024 तक लगभग 170 देश कनाडा के शहर ओटावा में प्लास्टिक प्रदूषण की तेजी से बढ़ती समस्या को रोकने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। विशेषज्ञों को इस बात की आशंका है कि क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से भावी पीढ़ियों को बचाएगा या यह झूठे समाधानों को और बढ़ावा देगा?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, हर दिन दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में 2,000 ट्रकों के बराबर प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। लोग तेजी से छोटे प्लास्टिक कणों को सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं। क्या इस संधि में लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गौर किया जाएगा, प्लास्टिक के वास्तविक उत्पादन को सीमित किया जाएगा, प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें देशों का एक स्व-नाम उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन देखना चाहता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि वार्ताकारों को मौजूदा संधि के मसौदे को सुव्यवस्थित करना चाहिए और उपरोक्त मुद्दों को तय करना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा इस बात की आशंका जताई जा रही है कि समझौते का दायरा सीमित हो सकता है और इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट तथा अधिक रीसाइक्लिंग या पुनर्चक्रण पर गौर किया जा सकता है, जैसा कि कुछ प्लास्टिक उत्पादक तथा तेल एवं गैस निर्यातक चाहते हैं। मार्च 2022 में, 175 देशों ने 2024 के अंत तक महासागरों सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि करने पर सहमति व्यक्त की। यह वार्ता के लिए एक बहुत ही छोटी समय सीमा है, जिसका उद्देश्य समस्या निपटना है। यह प्लास्टिक के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी वार्ता समिति की पांच बैठकों में से चौथी बैठक है। यूएनईपी की वेबसाइट के हवाले से यूएनईपी के कार्यकारी

निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, जब हम किसी ऐसी चीज को ठीक कर सकते हैं, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि उसे ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण में प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया भर में लोग जो कुछ भी देखते हैं, उससे घृणा करते हैं। कछुए की नाक में तिनका, मछली पकड़ने के उपकरणों से भरी व्हेल। मेरा मतलब है, यह वह दुनिया नहीं है, जिसमें हम रहना चाहते हैं।

एंडरसन ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि यह एक प्लास्टिक विरोधी प्रक्रिया है क्योंकि प्लास्टिक के कई उपयोग हैं जो दुनिया की मदद करते हैं। लेकिन, उन्होंने कहा कि संधि को अनावश्यक एक बार-उपयोग होने वाले और अल्पकालिक प्लास्टिक उत्पादों को खत्म करना चाहिए जिन्हें अक्सर दफनाया जाता है, जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और यदि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो अनुमान है कि 2050 तक यह दोगुना या तिगुना हो जाएगा। लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने पिछले सप्ताह जलवायु प्रभाव की जांच करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, रिपोर्ट में कहा गया कि यदि उत्पादन इसी तरह बढ़ता रहा, तो इस प्रक्रिया से उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन दोगुना से अधिक हो जाएगा। यह शेष वैश्विक कार्बन बजट का 21 से 26 फीसदी उपयोग कर सकता है, जो कि 1850 के दशक से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य पर या उससे नीचे रहते हुए अभी से 2050 के बीच कितना कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। ज्यादातर प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है। कॉप 28 के नाम से जानी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में वार्ताकारों ने पिछले दिसंबर में सहमति जताई थी कि दुनिया को गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधन से दूर जाना चाहिए और अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को तीन गुना बढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे जीवाश्म ईंधन को कम करने का दबाव बढ़ता गया, तेल और गैस कंपनियां अपने कारोबार के प्लास्टिक पक्ष को जीवन रक्षक के रूप में देख रही हैं, एक ऐसा बाजार जो बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने वार्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में तेल और गैस उत्पादक देशों को बताया है जो ऐसी संधि नहीं चाहते हैं जो प्लास्टिक बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन निकालने और निर्यात करने की उनकी क्षमता को सीमित करती हो। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें एक ऐसी संधि चाहिए जो प्लास्टिक में खतरनाक रसायनों पर वैश्विक नियंत्रण रखे और प्लास्टिक उत्पादन की तीव्र वृद्धि को रोके।

फल खाने वाले पक्षियों के बिना कार्बन जमा करने में आएगी 38 फीसदी की कमी - अध्ययन

कनाडा। अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि कम घने जंगल पक्षियों की आवाजाही को सिमित करते हैं, जिससे कार्बन रिकवरी की संभावना 38 फीसदी तक कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में 70 से 90 फीसदी पेड़ की प्रजातियां जानवरों द्वारा बीजों के फैलाने पर निर्भर हैं। फोटो साभार- विकिमीडिया कॉमन्स, मैट मैकगिलिव्रे एक नए शोध में उष्णकटिबंधीय जंगलों के प्राकृतिक पुनर्जनन में एक बड़ी रुकावट का पता चला है। ब्राजील के अटलांटिक जंगलों में एकत्रित जमीनी आंकड़े दिखाते हैं कि जब जंगली उष्णकटिबंधीय जंगलों में पक्षी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो वे पुनर्जीवित उष्णकटिबंधीय वनों के कार्बन भंडारण को 38 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं।

फल खाने वाले पक्षी जैसे कि रेड-लेग्ड हनीक्रीपर, पाम टैनेजर, या रूफस-बेलिड थ्रश वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे जंगलों में फलों को खाकर उनके बीजों को पूरे जंगल में फैलाते हैं। उष्णकटिबंधीय जंगलों में 70 से 90 फीसदी पेड़ की प्रजातियां जानवरों द्वारा बीजों के फैलाने पर निर्भर हैं। यह शुरुआती प्रक्रिया जंगलों को बढ़ने के लिए जरूरी है। जबकि पहले के अध्ययनों में कहा गया है कि पक्षी वन जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, शोधकर्ताओं को अब इस बात की समझ है कि वे जंगलों की बहाली में कैसे योगदान देते हैं।

नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में पेड़ों के दोबारा उगने में जंगली पक्षियों (फ्रुजीवोर्स) के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण मिलता है। शोधकर्ताओं ने कम घने जंगलों में कार्बन भंडारण क्षमता की तुलना बहुत कम घने जंगलों से की। आंकड़ों से पता चलता है कि कम घने जंगल पक्षियों की आवाजाही को सिमित करते हैं, जिससे कार्बन रिकवरी की संभावना 38 फीसदी तक कम हो जाती है। ब्राजील में अटलांटिक के जंगलों वाले इलाकों में, शोधकर्ताओं ने पाया कि न्यूनतम 40 फीसदी वन आवरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी पाया कि जंगल वाले इलाकों के बीच 133 मीटर या उससे कम की दूरी यह सुनिश्चित करती है कि पक्षी पूरे परिदृश्य में घूमते रहें और पारिस्थितिकी के पुनर्प्राप्ति में सहायता करें। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बीज फैलाव के मामले में अलग-अलग प्रभाव होता है। छोटे पक्षी अधिक बीज फैलाते हैं, लेकिन वे केवल कम कार्बन भंडारण क्षमता वाले पेड़ों से छोटे बीज ही फैला सकते हैं। इसके विपरीत, टोको टूकेन या कर्ल-क्रेस्टेड जे जैसे बड़े पक्षी भारी कार्बन भंडारण क्षमता वाले पेड़ों के बीज फैलाते हैं। समस्या यह है कि बड़े पक्षियों के अत्यधिक कमी वाले जंगलों में जाने की संभावना कम होती है। अध्ययन के हवाले से शोधकर्ता ने कहा, यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें जंगलों की सक्रिय बहाली प्रयासों, जैसे कि वृक्षारोपण को इस वन आवरण सीमा से नीचे वाले परिदृश्यों में शामिल करने में सक्षम बनाती है, जहां सहायता प्राप्त बहाली सबसे जरूरी और प्रभावी है। अध्ययन में शोधकर्ता ने कहा कि बड़े फलभक्षी जीवों को जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देना स्वस्थ उष्णकटिबंधीय जगलों को दोबारा हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन दर्शाता है कि विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पक्षियों के माध्यम से बीजों का फैलाव, उन प्रजातियों को निर्धारित करने में एक जरूरी भूमिका निभाता है जो पुनर्जीवित हो सकती हैं।

वर्तमान आंकड़ों के आधार पर, यह अध्ययन ब्राजील में अटलांटिक के जंगलों में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए पिछले जमीनी अध्ययनों से शोध को आगे बढ़ाता है। जंगल दुनिया के सबसे जैविक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है, लेकिन यह सबसे अधिक खंडित क्षेत्रों में से भी एक है, जिसमें मूल वन का केवल 12 फीसदी ही बचा है और यह छोटे क्षेत्रों में है।

यह जंगल बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक बहाली के लिए धरती पर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जिसमें अटलांटिक में जंगलों की बहाली संधि के तहत बहाली और प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति के लिए 1.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि चुनी गई है।

शोध से पता चलता है कि 40 फीसदी से अधिक जंगलों के इलाकों में वृद्धि न केवल प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, बल्कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगलों की बहाली करने की पहल की सफलता को बढ़ाने के लिए बीज फैलाव और कार्बन भंडारण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के कामकाज को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

अध्ययन में शोधकर्ता ने कहा, हम हमेशा से जानते हैं कि पक्षी आवश्यक हैं, लेकिन उन प्रभावों के पैमाने की खोज करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन जंगलों के भीतर जीवन की जटिलता को ठीक कर सकते हैं, तो उनकी कार्बन भंडारण क्षमता काफी बढ़ जाएगी।

उष्णकटिबंधीय जंगलों को दोबारा हासिल करने की रणनीतियां

पहले के शोध से पता चलता है कि जंगलों को दोबारा हासिल करने से अटलांटिक में जंगलों के इलाके में 2.3 अरब मीट्रिक टन से अधिक कार्बन को रोका जा सकता है और सक्रिय रोपण की तुलना में प्राकृतिक तरीके से पेड़ों के उगने से अधिक किफायती होने की संभावना है, जिससे इसे करने की लागत में 77 फीसदी तक की कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि फलों के पेड़ लगाने और अवैध शिकार को रोकने जैसी कई रणनीतियां उष्णकटिबंधीय इलाकों में जानवरों की आवाजाही को बढ़ा सकती हैं, जहां अपने आप बहाली की संभावना अधिक है। अत्यधिक खंडित जंगलों में सक्रिय बहाली आवश्यक है। बीजों के फैलाव की अनुमति देने वाले आस-पास के परिदृश्य में वन आवरण की पहचान करके, हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां प्राकृतिक तरीके से पेड़ों का पुनर्जनन संभव है, साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां हमें सक्रिय रूप से पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिससे हम जंगलों की बहाली को किफायती बना सकते हैं।

पृथ्वी दिवस 2024- साल 2040 तक सभी तरह के प्लास्टिक के उत्पादन में 60 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में अमेरिका के कॉलेज परिसरों में मनाया गया था, जब सांता बारबरा में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ था, उसके कुछ महीनो बाद इसकी शुरुआत की गई। तब से इस आंदोलन ने 192 से ज्यादा देशों में एक अरब से अधिक लोगों को संगठित किया है।

क्या है विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम?- आज, यानी सोमवार को विश्व पृथ्वी दिवस के वार्षिक कार्यक्रम में 'ग्रह बनाम प्लास्टिक' की वैश्विक थीम के साथ मनाया जा रहा है। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के अनुसार, दुनिया भर में हर साल 38 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक के कचरे का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से काफी मात्रा लैंडफिल, महासागरों और जलमार्गों में पहुंच जाती है। अर्थडे.ऑर्ग में कहा गया है कि वह, लोग और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है, तथा 2040 तक सभी प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में 60 फीसदी की कमी की आह्वान करता है। विश्व पृथ्वी दिवस के दौरान, प्लास्टिक के कारण मानव, पशु और समस्त जैव विविधता के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में व्यापक सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना और इसके स्वास्थ्य प्रभावों पर अधिक शोध किए जाने की मांग करना। जिसमें इसके प्रभावों के बारे में सभी जानकारी जनता को देना शामिल है। साल 2030 तक एक बार उपयोग होने वाले सभी तरह के प्लास्टिक को तेजी से समाप्त करना और 2024 में प्लास्टिक प्रदूषण पर संयुक्त राष्ट्र संधि में इस चरणबद्ध समाप्ति प्रतिबद्धता को हासिल करना है। फास्ट फैशन और इसके द्वारा उत्पादित और उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की भारी मात्रा के संकट को समाप्त करने वाली नीतियों की

मांग करना। प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाने के लिए नवीन तकनीकों और सामग्रियों में निवेश करना। लगभग 85 फीसदी कपड़े लैंडफिल में छोड़ दिए जाते हैं, जिनमें से केवल एक फीसदी का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। लगभग 70 फीसदी कपड़े कच्चे तेल से बने होते हैं, जिसके कारण उन्हें धान पर खतरनाक माइक्रोफाइबर निकलते हैं और लैंडफिल में लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते हैं।

पृथ्वी दिवस की शुरुआत कैसे हुई?- कैलिफोर्निया तट पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के कुछ महीनों बाद अमेरिका में पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई। अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने इस दौरान छात्रों के विरोध करनेकी ऊर्जा को वायु और जल प्रदूषण के बारे में उभरती हुई सार्वजनिक चेतना के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के लिए 22 अप्रैल की तारीख चुनी थी, जिसे आमतौर पर जलवायु और पर्यावरण आंदोलन के इतिहास में हस्ताक्षरित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। उस वर्ष 22 अप्रैल को 196 देशों के नेता दुनिया भर में बढ़ते तापमान के खिलाफ कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को अपनाने के लिए एक साथ आए थे। देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)= एसडीजी 13, जलवायु कार्रवाई और एसडीजी 15, भूमि पर जीवन, जलवायु कार्रवाई और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और सभी के लिए एक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य हासिल करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है।

पेयजल स्त्रोतों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता रखी जाए: श्री तोमर

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने सोमवार को कंपनी के विभाग प्रमुखों की बैठक में निर्देश दिए कि मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों में लोकसभा चुनाव में बूथों की बिजली व्यवस्था को लेकर गंभीरता बरती जाए। यदि किसी बूथ पर बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं है, तो वहां अस्थाई कनेक्शन मतदान से दो-तीन दिन पूर्व हर हाल में दिया जाए। श्री तोमर ने निर्देश दिए कि कंपनी के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी से सतत संपर्क में रहे। श्री तोमर ने कहा कि मतदान सामग्री स्थल, ईवीएम स्टोर रूम, प्रशिक्षण स्थल व लोक सभा चुनाव से जुड़े अन्य शासकीय कार्यालयों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल स्त्रोतों की बिजली वितरण व्यवस्था पर सतत निगाह रखने को कहा, उन्होंने कहा कि बिजली के कारण कही व्यवस्था प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक श्री रिंकेश कुमार वैश्य, निदेशक श्री पुनीत दुबे, कार्यपालक निदेशक आपूर्ति श्री गजरा मेहता, मुख्य अभियंता इंदौर श्री एसआर बमनके, श्री एसएल करवाड़िया, श्री एसआर सेमिल, श्री आरके कार्य, मुख्य वित्त अधिकारी श्री नरेंद्र बिवालकर आदि ने भी विचार रखें।

भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान

भोपाल (एजेंसी) मध्यप्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के एक्टिव होने से आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। सोमवार को भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। धार में दोपहर 12.54 बजे 10 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे। इंदौर में घने बादल छाए हैं। कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई। बड़वानी जिले के सेंधवा में कड़वा झिरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बच्चे (5) की मौत हो गई। घायल महिला का इलाज सेंधवा सिविल अस्पताल में चल रहा है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे, यानी सोमवार को जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 17 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। सीनियर वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होगी। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 25 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ेगी। जिन शहरों में अभी 40-42 डिग्री टेम्प्रेचर है, वहां 42 से 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। रातें भी गर्म रहेंगी। वहीं, उमस का असर भी दिखाई देगा। पिछले 3 दिन से कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। ˙ भोपाल में सोमवार सुबह बारिश हुई। चार इमली, न्यू मार्केट, एमपी नगर इलाके में बारिश से सडक़ें तरबतर हो गई। सुबह से शहर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान जताया है। अगले 3 दिन तक बादल भी रहेंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 21 जिलों के 51 शहर-कस्बों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इनमें भोपाल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, जबलपुर, सिवनी, बैतूल, रायसेन, कटनी, डिंडोरी, विदिशा, नर्मदापुरम, गुना, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सागर, दमोह और अनूपपुर जिले शामिल हैं। सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा के तामिया और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में आधा इंच से अधिक हुई। खरगोन के बड़वाह में भी पानी गिरा। मौसम बदलने से यहां बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई।

एनजीटी ने सभी राज्यों से मांगा उनके वन क्षेत्र पर हुए अतिक्रमण का लेखा-जोखा

नई दिल्ली (एजेंसी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन अतिक्रमण के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 19 अप्रैल को दिए आदेश के दायरे में संरक्षित, आरक्षित, डीम्ड वन, अभयारण्य और अन्य सभी प्रकार के वन शामिल हैं। उनसे मार्च 2024 तक वन क्षेत्र को जो हानि हुआ है, उसका विवरण भी प्रतिशत में देने को कहा है।

ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने जवाब की एक प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजनी के लिए भी कहा है। इसके साथ ही इसकी एक प्रति ट्रिब्यूनल में भी जमा करनी होगी। अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सभी जानकारियों को एकत्र करने के लिए भी कहा है।

गौरतलब है कि यह मामला देशभर में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर होते अतिक्रमण से जुड़ा है। पिछली कार्यवाही में ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य पर गौर किया था कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अतिक्रमण के कारण वन क्षेत्र 56 फीसदी तक गिर गया है। मछलियों में फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग को रोकने के लिए क्या की गई कार्रवाई, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मांगी जानकारी गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2024 को कामरूप के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के अनुसार इसमें मछलियों में फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार मत्स्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण होना चाहिए। गौरतलब है कि इस बारे में असम सरकार द्वारा नौ फरवरी, 2024 को एक और हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में जानकारी दी गई थी कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों (एसओपी) को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है और उसे अधिसूचित कर दिया गया है। इसे 20 जनवरी, 2024 से लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा फार्मल्डिहाइड के उपयोग के मुद्दे को संबोधित करना है। इसके तहत एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क या नदी द्वारा परिवहन के दौरान मछली को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग को सीमित करना है।

उच्च न्यायालय ने इस हलफनामे को तीन सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा है। इसमें 20 जनवरी को जारी एसओपी के तहत सौंपी गई एजेंसियों के परीक्षण परिणाम होने चाहिए। साथ ही इसमें मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े भी दिए जाने चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई 2024 को होगी। यह निर्देश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने जारी किए हैं।

बता दें कि इस मामले में एनजीटी की पूर्वी बेंच ने 10 अप्रैल, 2024 को असम के सरकारी अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था।

मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि एसओपी में कई खामियां हैं। उनके मुताबिक 2023 में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मत्स्य पालन कॉलेज, गौहाटी विश्वविद्यालय, नागांव कॉलेज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और जिला मत्स्य विभाग अधिकारियों जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए निरीक्षणों में भिन्नता है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जहां अन्य एजेंसियों को दूसरे राज्यों से आयात की गई मछलियों में फॉर्मेल्डिहाइड मिला है, वहीं मत्स्य विभाग ने अपने सर्वेक्षण में कहा है कि सभी नमूने ठीक थे। ऐसे में याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल राज्य ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र एजेंसी से उनकी रिपोर्ट लेना महत्वपूर्ण है।

पृथ्वी को हरा भरा करने का संदेश देने हेतु महिला संघ द्वारा बालिकाओं की साईकिल रैली

(महू)पृथ्वी एनएन बालिकाओं के लिए एक साईकिल रैली का आयोजन 24 अप्रेल बुधवार प्रात: 7 बजे सामाजिक संस्था महिला संघ द्वारा किया गया है जिसमें 10 विद्यालय की बालिकाएं एवं अन्य भी अपनी भागीदारी निभा कर धरती मां को पोल्यूशन मुक्त करने का संदेश देते हुए , सी बी कन्या विद्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गो से होते हुए सी बी कन्या विद्यालय पर ही समाप्त होगी ।आओ मिलकर वसुंधरा को हरा भरा बनाएं अपना भरपूर योगदान देकर धरती मां को पोल्यूशन मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास करें। स्लोगन द्वारा बालिकाएं साइकल पर अपना संदेश देते हुए रैली में शामिल होंगी कार्यक्रम की संयोजिका शकुंतला विजयवर्गीय, निर्मला यादव, कान्ता सोढानी, अंशु गुप्ता ,सरिता खंडेलवाल, राजकुमारी अग्रवाल आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008